



ISSN: 2395-7852



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 4, July 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462

+91 9940572462

ijarasem@gmail.com

www.ijarasem.com



विनिवेश नीति - चुनौतियां एवं संभावनाएं

Dr.Nitin Kumar

Dept. of Commerce, Government Model Degree College, Kapoori, Govindpur, Saharanpur, Uttar Pradesh, India

सार

भारत में विनिवेश भारत सरकार की एक नीति है, जिसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी संपत्ति का परिसमापन करती है। आंशिक रूप से या पूर्णतः। विनिवेश का निर्णय मुख्य रूप से राजकोषीय बोझ को कम करने और सरकार के राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए है। स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास हासिल करने में मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) द्वारा निभाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद पीएसई की अन्य जिम्मेदारियों में, राष्ट्र के सामाजिक और विकासात्मक दायित्व सबसे महत्वपूर्ण थे, जिसके परिणामस्वरूप ये इकाइयाँ प्रतिस्पर्धी दौड़ से बच गईं। बाद में पीएसई की गतिविधियाँ अलग-अलग हो गईं, उनका ध्यान होटल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हो गया। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यमों को राजनीतिक और नौकरशाही हेरफेर के उपकरण के रूप में उपयोग किया गया था; जिसके परिणामस्वरूप कम क्षमता उपयोग, कम उत्पादकता, नवप्रवर्तन में विफलता और विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जटिल निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ हुईं।

1980 के दशक के अंत तक, पीएसई की वृद्धि, जैसा कि कुछ टिप्पणीकारों ने व्यक्त किया था, "अपने आप में अंत" में बदल गई थी। ये कारक भारत के विकास में बाधक बने। इसलिए, पीएसई के खराब प्रदर्शन ने भारत के विकास में कमजोरी को दूर करने के लिए सुधारों की मांग की। 1991 में सरकार बदलने के बाद शुरू किये गये कई आर्थिक सुधारों में; निजीकरण एक था, जो सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी को कम करके और राजकोषीय मितव्ययता लाकर राज्य के राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर केंद्रित था।^[1]

परिचय

स्वतंत्रता-पूर्व युग के दौरान औपनिवेशिक सरकारों की आर्थिक नीतियां मुख्य रूप से भारत के बजाय अपने गृह देश को बढ़ावा देने पर केंद्रित थीं। इसलिए, अधिकांश औद्योगिक गतिविधि कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटेन से तैयार उत्पादों के आयात पर केंद्रित थी। आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक और औद्योगिक नीति सोवियत संघ की तर्ज पर बनाई गई, जिसे 'समाजवादी ढाँचा' कहा गया। हालाँकि, औद्योगीकरण की इस समाजवादी नीति ने अधिकांश निजी उद्यमों को इसके संचालन पर कठोर प्रतिबंधों के साथ विनियमित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक अप्रभावी औद्योगिक प्रणाली को आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र और भुगतान संतुलन का निराशाजनक प्रदर्शन 1991 के संकट ने नीति निर्माताओं को स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने और एक और खुले बाजार उन्मुख नीति की दिशा में सुधार कार्यक्रम करने के लिए मजबूर किया।^[2]

अधिदेश

1996 में, भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय के तहत एक विनिवेश आयोग की स्थापना की; आयोग का कार्य व्यवहार्यता का आकलन करना और बाजार विकास के माध्यम से विभिन्न पीएसई के विनिवेश और पांच-दस साल की अवधि के लिए पीएसई के स्वामित्व के विविधीकरण हस्तांतरण पर सरकार को सलाह देना था।^[3] 10 दिसंबर 1999 को, आयोग को भंग कर दिया गया और भारत में विनिवेश पर सभी निर्णय वित्त मंत्रालय के तहत गठित एक अलग विनिवेश विभाग द्वारा लिए गए। 2001 में, वाजपेयी सरकार ने विनिवेश विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय में अपग्रेड कर दिया। लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लिए गए कई निर्णयों में से पहला निर्णय मंत्रालय को बंद करना और इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में वित्त मंत्रालय में विलय करना था।^[4] बाद में, 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) कर दिया गया।^[5]



DIPAM का अधिदेश इस प्रकार है:

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।
- पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बिक्री प्रस्ताव या निजी प्लेसमेंट या किसी अन्य माध्यम से केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले।

विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामले, जिनमें पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक भागीदार द्वारा कॉल विकल्प के प्रयोग से संबंधित और उससे उत्पन्न मामले भी शामिल हैं, को प्रशासनिक मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा, जहां आवश्यक हो, परामर्श से नियंत्रित किया जाता रहेगा। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)।^[5]

विनिवेश नीतियां

विनिवेश पर नीति संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन और वित्त मंत्री के बजट भाषणों के माध्यम से काफी विकसित हुई है।^[6]

1991 से 1999

देश में आर्थिक सुधारों और पीएसयू के प्रदर्शन को फिर से परिभाषित करने के लिए, 1991 में एक नई औद्योगिक नीति तैयार की गई, जिसमें पीएसयू की भूमिका पर चर्चा की गई और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए एक व्यापक नीति बनाई गई। इस नीति ने पीएसयू बोर्डों को स्वायत्तता प्रदान की और उन्हें अपने संचालन में दक्षता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पीएसयू की पहचान की और उन पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में घाटे में चल रही अधिकांश संस्थाओं का निजीकरण कर दिया। औद्योगिक पुनर्गठन के तहत, सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों को निजी संस्थाओं के लिए खोल दिया। जबकि, सार्वजनिक क्षेत्र ने रेलवे, खनन और परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1991 की नीति की एक अन्य प्रमुख संभावना "लालफीताशाही" को समाप्त करना था जिसे औद्योगिक लाइसेंसिंग के रूप में जाना जाता था। जिसमें निजी क्षेत्र का उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। जिससे किसी भी निजी संस्था द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित करने में होने वाली अनावश्यक देरी में कमी आएगी।^[7]

औद्योगिक नीति वक्तव्य की प्रमुख उपलब्धियों में से एक, जैसा कि 1992 के केंद्रीय बजट में दर्शाया गया था: इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को सत्रह से घटाकर चार कर दिया।^[8] इसके अलावा, पीएसयू के लिए बजटीय प्रावधानों में तेजी से कटौती की गई और घाटे में चल रहे अधिकांश उद्यमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेज दिया गया। सी. रंगराजन की अध्यक्षता में विनिवेश के लिए दिशानिर्देश विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। आयोग ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की गई: सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कंपनियों में 49 प्रतिशत तक और अन्य संस्थाओं में 100 प्रतिशत तक विनिवेश की अनुमति दी जाए।^[8]

1999 से 2004

1999-2004 के दौरान वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विनिवेश नीति ने देश में विनिवेश प्रक्रिया को तेज कर दिया। सरकार ने विनिवेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, यह वही सरकार थी जिसने निजीकरण शब्द का प्रयोग किया था "पहली बार विनिवेश के स्थान पर। सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली नई पद्धति, सार्वजनिक उपक्रमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना था: "रणनीतिक" और "गैर-रणनीतिक"; रक्षा-संबंधी उपकरणों से संबंधित सभी उद्योग थे इन्हें रणनीतिक संसाधनों के रूप में वर्णित किया गया था और इन क्षेत्रों के लिए किसी विनिवेश की सिफारिश नहीं की गई थी। जबकि, अन्य सभी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी हिस्सेदारी को घटाकर 26 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया था। एनडीए सरकार की नीति रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करके उन्हें मजबूत करना था। गैर-रणनीतिक कंपनियां। सरकार ने जरूरत पड़ने पर 26 प्रतिशत या उससे कम तक गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया।^[9] वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए कार्यकाल को देखते हुए, कुछ आर्थिक विद्वानों ने विनिवेश की दिशा में पिछली एनडीए



सरकार के प्रयासों की सराहना की है और कहा है: "दिवंगत प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान विनिवेश नीति ने एक स्वर्णिम काल देखा"।^[10]

2004 से 2014

अब तक, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-1 और यूपीए-11 सरकारें 2004 से 2014 तक सत्ता में थीं; DIPAM के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम में पर्याप्त रुचि नहीं ली और भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी को बाधित कर दिया।^[10]^[11] 2004 में यूपीए-1 सरकार ने एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) तैयार किया, जिसमें उसने विनिवेश के प्रति अपनी नीति को संक्षेप में प्रस्तुत किया। (एनसीएमपी) के कुछ अंश घोषित: किसी भी लाभ कमाने वाले उद्यम का निजीकरण नहीं किया जाएगा, सभी नवरत्न कंपनियों को पूंजी बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए बनाए रखा जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा, सभी घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा और लंबे समय से बीमार उद्योगों को बेच दिया जाएगा, कार्यबल को उचित मुआवजा दिया जाएगा, निजीकरण से उत्पन्न सभी राजस्व का भुगतान किया जाएगा चयनित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। यूपीए सरकार ने कई अन्य निर्णयों में से सबसे पहले पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की "रणनीतिक बिक्री" नीति की प्रक्रिया को बंद कर दिया; और विशेष रूप से कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पमत हिस्सेदारी की नीलामी की गई।^[12]

विनिवेश का प्रभाव

जबकि भारत में विनिवेश का अभ्यास बड़े पैमाने पर एक निजी इकाई को सीमित सीमा तक इकटिरी हस्तांतरित करके किया जाता है, न कि सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व का पूर्ण हस्तांतरण करके। इस प्रकार, कुछ पर्यवेक्षकों ने "आंशिक निजीकरण" शब्द का उपयोग ऐसे लेनदेन के लिए बेहतर उपयुक्त के रूप में किया है।^[13] डॉ. सुधीर नायब ने भारत में विनिवेश: नीतियां, प्रक्रियाएं, प्रथाएं नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, "सरकार धीरे-धीरे विनिवेश से निजीकरण की ओर बढ़ गई है।" इसके अलावा, अपने शोध के माध्यम से, लेखक ने पाया है कि, जब भी किसी सार्वजनिक उपक्रम में विनिवेश के माध्यम से निजी संस्थाओं को स्वामित्व का हस्तांतरण होता था, तो संबंधित उद्यम की आर्थिक दक्षता में सुधार होता था।^[14] इसी तरह, हरजीत सिंह ने अपनी पुस्तक में शीर्षक दिया है विनिवेश के माध्यम से कॉर्पोरेट पुनर्गठन (एक भारतीय परिप्रेक्ष्य) लिखते हैं; अल्पांश विनिवेश के बाद पीएसयू के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि कंपनी का प्रबंधकीय नियंत्रण वहीं बना रहा। इसलिए, लेखक नोट करता है: यह विनिवेश का आकार नहीं है जो दक्षता में सुधार करता है, बल्कि कंपनी के नेतृत्व में बदलाव और नवाचार, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसे अन्य बाजार प्रेरक कारक आर्थिक दक्षता को प्रभावित करते हैं।^[15]

विनिवेश की राजनीति

जैसा कि विनिवेश की प्रक्रिया सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य के स्वामित्व को कमजोर करती है, कुछ विद्वानों ने देखा है, विभिन्न राजनीतिक कारक भी विनिवेश नीतियों से निपटने में बाधा बन सकते हैं।^[16] जैन और सरकार ने 2017 में किए गए अपने शोध में पाया: जब वाम-झुकाव वाले दलों की तुलना में समान विचारधारा वाले गठबंधन दलों सहित एक दक्षिण-झुकाव वाले राजनीतिक दल द्वारा विनिवेश किया जाता है, तो विनिवेश अधिक होता है। अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि विचारधाराओं में केंद्र और राज्य जितना अधिक एकजुट होंगे, विनिवेश की संभावनाओं में काफी सुधार होगा।^[17] कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विनिवेश नीति को मूल रूप से लागू न करने का कारण 2004 के आम चुनावों के बाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत न होना था। परिणामस्वरूप सीपीआई-एम जैसी वामपंथी झुकाव वाली पार्टियों के बाहरी समर्थन पर उनकी निर्भरता बढ़ गई, जिसके कारण सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि दोनों पार्टियों की अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग विचारधाराएं थीं।^[18]

विचार-विमर्श

एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम (एसओई) एक सरकारी इकाई है जिसे सरकार के लिए लाभ कमाने, निजी क्षेत्र के एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए, एक कार्यकारी आदेश या कानून के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार द्वारा स्थापित या राष्ट्रीयकृत किया जाता है। संस्थाएँ, नागरिकों को कम कीमत पर उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती हैं, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करती हैं और देश के दूरस्थ स्थानों तक उत्पाद और सेवाएँ पहुँचाती हैं। इन राज्य स्वामित्व



वाले उद्यमों पर राष्ट्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार का बहुमत स्वामित्व है। इन राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में भी जाना जाता हैकुछ देशों में। [1] एसओई की परिभाषित विशेषताएं उनका विशिष्ट कानूनी रूप और वित्तीय लक्ष्यों और विकासात्मक उद्देश्यों पर कब्जा है (उदाहरण के लिए, एक राज्य रेलवे कंपनी का लक्ष्य परिवहन को अधिक सुलभ बनाना और सरकार के लिए लाभ कमाना हो सकता है), एसओई वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए स्थापित की गई सरकारी संस्थाएं हैं। उद्देश्य और विकासात्मक लक्ष्य। [2]

राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम शब्द से संबंधित शब्दावली अस्पष्ट है। शब्द के सभी तीन शब्दों को चुनौती दी गई है और वे व्याख्या के अधीन हैं। सबसे पहले, यह बहस का विषय है कि "राज्य" शब्द का क्या तात्पर्य है (उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट नहीं है कि नगरपालिका के स्वामित्व वाले निगम और क्षेत्रीय सार्वजनिक निकायों द्वारा संचालित उद्यमों को राज्य के स्वामित्व वाला माना जाता है या नहीं)। इसके बाद, यह विवादास्पद है कि किन परिस्थितियों में एक एसओई किसी राज्य के "स्वामित्व" के रूप में योग्य होता है (एसओई पूरी तरह से स्वामित्व में या आंशिक रूप से स्वामित्व में हो सकता है; यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करना मुश्किल है कि राज्य के स्वामित्व का कौन सा स्तर किसी इकाई को राज्य के स्वामित्व के रूप में माना जाएगा) चूंकि सरकारें भी नियमित स्टॉक की मालिक हो सकती हैं, बिना किसी विशेष हस्तक्षेप के)। अंत में, "उद्यम" शब्द को चुनौती दी गई है, क्योंकि इसका तात्पर्य निजी कानून में कानून से है जो हमेशा मौजूद नहीं हो सकता है, और इसलिए इसके बजाय "निगम" शब्द का उपयोग अक्सर किया जाता है। [3] [4]

इस प्रकार, एसओई को कई अन्य शब्दों के तहत जाना जाता है: राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी, राज्य के स्वामित्व वाली इकाई, राज्य उद्यम, सार्वजनिक स्वामित्व वाला निगम, सरकारी व्यवसाय उद्यम, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, सरकार के स्वामित्व वाला निगम, सरकार प्रायोजित उद्यम, वाणिज्यिक सरकारी एजेंसी , राज्य-निजीकृत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, या पैरास्टेटल, अन्य। राष्ट्रमंडल क्षेत्रों में , विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में, देश-व्यापी एसओई अक्सर "क्राउन कॉरपोरेशन" या " क्राउन इकाई " शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री (क्राउन के मंत्री) अक्सर नियंत्रण करते हैं। उनमें शेयर.

शब्द " सरकार से जुड़ी कंपनी " (जीएलसी) का उपयोग कभी-कभी किया जाता है, उदाहरण के लिए मलेशिया में , [5] निजी या सार्वजनिक (स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध) कॉर्पोरेट संस्थाओं को संदर्भित करने के लिए जिसमें सरकार एक होल्डिंग कंपनी का उपयोग करके हिस्सेदारी हासिल करती है । जीएलसी की दो मुख्य परिभाषाएँ सरकार के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाई के अनुपात पर निर्भर हैं। एक परिभाषा का तात्पर्य है कि एक कंपनी को जीएलसी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि सरकार के पास प्रभावी नियंत्रण हित (50% से अधिक) है, जबकि दूसरी परिभाषा [उद्धरण वांछित] सुझाव है कि कोई भी कॉर्पोरेट इकाई जिसमें शेयरधारक के रूप में सरकार हो, जीएलसी है। सरकारी नौकरशाही के एक हिस्से को एसओई में बदलने की क्रिया को निगमीकरण कहा जाता है । [6] [7] [8]

आर्थिक सिद्धांत में, यह सवाल कि क्या किसी फर्म का स्वामित्व राज्य के पास होना चाहिए या निजी क्षेत्र के पास, ओलिवर हार्ट और उनके सह-लेखकों द्वारा विकसित अधूरे अनुबंधों के सिद्धांत में अध्ययन किया गया है। [9] ऐसी दुनिया में जहां पूर्ण अनुबंध संभव थे, स्वामित्व कोई मायने नहीं रखता क्योंकि एक स्वामित्व संरचना के तहत प्रचलित समान प्रोत्साहन संरचना को अन्य स्वामित्व संरचना के तहत दोहराया जा सकता है। हार्ट, श्लीफर और विश्नी (1997) ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के मुद्दे पर अपूर्ण अनुबंध सिद्धांत का अग्रणी अनुप्रयोग विकसित किया है। [10] ये लेखक उस स्थिति की तुलना करते हैं जिसमें सरकार एक फर्म के नियंत्रण में होती है, उस स्थिति से जिसमें एक निजी प्रबंधक नियंत्रण में होता है। प्रबंधक लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने वाले नवाचार लाने के लिए निवेश कर सकता है। सरकार और प्रबंधक नवाचारों के कार्यान्वयन पर सौदेबाजी करते हैं। यदि वार्ता विफल हो जाती है, तो मालिक कार्यान्वयन के बारे में निर्णय ले सकता है। यह पता चला है कि जब लागत कम करने वाले नवाचार गुणवत्ता को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो निजी कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर भी, जब लागत में कटौती से गुणवत्ता में भारी कमी आ सकती है, तो राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम बेहतर होते हैं। हॉप और शमित्ज़ (2010) ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विभिन्न रूपों सहित शासन संरचनाओं के एक समृद्ध सेट की अनुमति देने के लिए इस सिद्धांत का विस्तार किया है । [11]



परिणाम

आर्थिक कारणों से

प्राकृतिक एकाधिकार

एसओई प्राकृतिक एकाधिकार के साथ आम हैं, क्योंकि वे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करने की अनुमति देते हैं जबकि वे एक साथ सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से, एसओई मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे (जैसे रेलवे कंपनियों), रणनीतिक वस्तुओं और सेवाओं (जैसे डाक सेवाओं, हथियार निर्माण और खरीद), प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा (जैसे परमाणु सुविधाएं, वैकल्पिक ऊर्जा वितरण), राजनीतिक रूप से संवेदनशील व्यवसाय के क्षेत्र में काम करते हैं।, प्रसारण, बैंकिंग, अवगुण वस्तुएँ (जैसे मादक पेय), और योग्यता वस्तुएँ (स्वास्थ्य सेवा)।

प्रारंभिक अवस्था वाले उद्योग

एसओई उन उद्योगों को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकते हैं जिन्हें "आर्थिक रूप से वांछनीय माना जाता है और जिन्हें अन्यथा निजी निवेश के माध्यम से विकसित नहीं किया जाएगा"। [12] जब नवजात या 'शिशु' उद्योगों को निजी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करने में कठिनाई होती है (शायद इसलिए कि जो उत्पाद उत्पादित किया जा रहा है, उसके लिए बहुत जोखिम भरे निवेश की आवश्यकता होती है, जब पेटेंट करना मुश्किल होता है, या जब स्पिलओवर प्रभाव मौजूद होते हैं), सरकार इन उद्योगों की मदद कर सकती है सकारात्मक आर्थिक प्रभाव के साथ बाजार में उतरें। हालाँकि, सरकार आवश्यक रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकती है कि कौन से उद्योग ऐसे 'शिशु उद्योगों' के रूप में योग्य होंगे, और इसलिए यह किस हद तक एसओई के लिए एक व्यवहार्य तर्क है, इस पर बहस चल रही है। [13]

राजनीतिक कारण

एसओई को अक्सर उन क्षेत्रों में भी नियोजित किया जाता है जहां सरकार उपयोगकर्ता शुल्क लगाना चाहती है, लेकिन नए कराधान को लागू करना राजनीतिक रूप से कठिन है। इसके बाद, एसओई का उपयोग सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता में सुधार करने या (आंशिक) निजीकरण या संकरण की दिशा में एक कदम के रूप में किया जा सकता है। एसओई राजकोषीय तनाव को कम करने का एक साधन भी हो सकता है, क्योंकि एसओई को राज्यों के बजट में नहीं गिना जा सकता है।

प्रभाव

सरकारी नौकरशाही की तुलना में

सरकारी नौकरशाही की तुलना में, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि वे सेवा पर राजनेताओं के प्रभाव को कम करते हैं। [14] [15] इसके विपरीत, वे हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि वे निरीक्षण को कम करते हैं और लेनदेन लागत को बढ़ाते हैं (जैसे निगरानी लागत, यानी, सार्वजनिक नौकरशाही की तुलना में एक स्वायत्त एसओई को नियंत्रित और विनियमित करना अधिक कठिन और महंगा है)। साक्ष्य बताते हैं कि मौजूदा एसओई आमतौर पर सरकारी नौकरशाही की तुलना में अधिक कुशल हैं, लेकिन यह लाभ कम हो जाता है क्योंकि सेवाएं अधिक तकनीकी हो जाती हैं और सार्वजनिक उद्देश्य कम होते हैं। [4]

नियमित उद्यमों की तुलना में

एक नियमित उद्यम की तुलना में, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से आम तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कम कुशल होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन लाभ-संचालित उद्यमों के विपरीत वे सरकारी उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखते हैं। [15]

दुनिया भर में

यूरोप में एसओई

पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में, पूरे 20वीं शताब्दी में, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण हुआ। पूर्वी ब्लॉक में, देशों ने यूएसएसआर के समान ही नीतियां और मॉडल अपनाए। पश्चिमी यूरोप में केंद्र के बाएँ और दाएँ दोनों सरकारों ने युद्ध से ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक माना। [16] उद्योग जैसे प्राकृतिक एकाधिकार पर सरकारी नियंत्रण आदर्श था। विशिष्ट क्षेत्रों में टेलीफोन, विद्युत शक्ति, जीवाश्म ईंधन, लौह अयस्क, रेलवे शामिल हैं, एयरलाइंस, मीडिया, डाक सेवाएं, बैंक और पानी। कई बड़े औद्योगिक निगमों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया या उन्हें सरकारी निगमों के रूप में बनाया गया, जिनमें कई अन्य शामिल हैं: ब्रिटिश स्टील कॉर्पोरेशन, स्टेटोइल और आयरिश शुगर। [17]



एक राज्य-संचालित उद्यम एक सामान्य सीमित देयता निगम से अलग तरीके से काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, फ़िनलैंड में, राज्य-संचालित उद्यम (liikelaitos) एक अलग कानून द्वारा शासित होते हैं। अपने स्वयं के वित्त के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है ; राज्य देनदारियों के लिए जवाब देता है। निगम के स्टॉक बेचे नहीं जाते हैं और ऋणों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सरकारी देनदारियां हैं।

राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम बेलारूस की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक हैं । [18] बेलारूसी राज्य के स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था में वे उद्यम शामिल हैं जो पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व वाले हैं, साथ ही अन्य जो राज्य के आंशिक स्वामित्व वाली संयुक्त स्टॉक कंपनियां हैं। [17] राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य-नियंत्रित उद्यमों में रोजगार कुल रोजगार का लगभग 70% है। [18] इस प्रकार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम बेलारूस की उच्च रोजगार दर और स्थिर रोजगार के स्रोत के पीछे एक प्रमुख कारक हैं। [10]

ओपेक देशों के बीच एसओई

अधिकांश ओपेक देशों में, सरकारें अपनी धरती पर काम करने वाली तेल कंपनियों की मालिक हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी , सऊदी अरामको है , जिसे सऊदी सरकार ने 1988 में खरीदा था, और इसका नाम अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी से बदलकर सऊदी अरब ऑयल कंपनी कर दिया था। सऊदी सरकार सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की भी मालिक है और उसका संचालन करती है, और SABIC के साथ-साथ कई अन्य कंपनियों की भी 70% हिस्सेदारी रखती है । 'उद्धरण वांछित'

चीन में एसओई

चीन के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग (एसएसएस) द्वारा किया जाता है । [11] चीन के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम आम तौर पर सार्वजनिक सेवाओं, संसाधन निष्कर्षण या रक्षा के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं। [11] 2017 तक, चीन में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक SOE हैं, और बड़ी राष्ट्रीय कंपनियों में सबसे अधिक SOE हैं।

चीन के एसओई ऐसे कार्य करते हैं: लाभांश और करों के माध्यम से केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के राजस्व में योगदान करना, शहरी रोजगार का समर्थन करना, प्रमुख इनपुट कीमतों को कम रखना, लक्षित उद्योगों और प्रौद्योगिकियों की ओर पूंजी लगाना, गरीब आंतरिक और पश्चिमी प्रांतों में उप-राष्ट्रीय पुनर्वितरण का समर्थन करना, और प्राकृतिक आपदाओं, वित्तीय संकटों और सामाजिक अस्थिरता के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया में सहायता करना। [12]

चीन के एसओई वैश्विक बंदरगाह-निर्माण में सबसे आगे हैं, और उनके द्वारा निर्मित अधिकांश नए बंदरगाह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तत्वावधान में किए जाते हैं । [13]

भारत में एसओई

भारत में , सरकारी उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के रूप में मौजूद हैं ।

मलेशिया में सरकार से जुड़ी कंपनियाँ

मलेशियाई सरकार ने 29 जुलाई 2005 को अपनी संबद्ध कंपनियों और संबद्ध निवेश कंपनियों ("जीएलआईसी") के लिए एक जीएलसी परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य दस साल की अवधि में इन व्यवसायों को "उच्च प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं" में बदलना है। जीएलसी उच्च प्रदर्शन ("पीसीजी") पर पुत्रजया समिति, जो इस कार्यक्रम की देखरेख करती थी, की अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी , और इसकी सदस्यता में वित्त मंत्री II, प्रधान मंत्री के विभाग में आर्थिक योजना इकाई के प्रभारी मंत्री शामिल थे। सरकार के मुख्य सचिव, ट्रेजरी के महासचिव और प्रत्येक जीएलआईसी (कर्मचारी भविष्य निधि, खज़ाना नेशनल बेरहाद , लेम्बागा तबुंग अंगकाटन टेंटेरा) के प्रमुख(सशस्त्र बल पेंशन फंड), लेम्बागा ताबुंग हाजी और परमोडालन नेशनल बरहाद । खज़ाना नेशनल बरहाद ने पीसीजी को सचिवालय प्रदान किया और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रबंधन किया, जो 2015 में पूरा हुआ। [24]

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः सभी देश एक दूसरे के साथ माल का आयात निर्यात करते हैं, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं और राशि का लेन देन भी करते हैं। इस प्रकार एक निश्चित अवधि के पश्चात् इन सभी मदों पर लेन देन का यदि हिसाब निकाला जाय तो किसी एक देश को दूसरे से भुगतान लेना शेष होता है और दूसरे देश को किसी किसी तीसरे देश का भुगतान चुकाना शेष रहता है। विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार के परस्परिक लेन देन के शेष को भुगतान शेष (Balance of payments) कहते



हैं। यों कहना चाहिए कि किसी निश्चित तिथि को एक देश द्वारा अन्य देशों को चुकाई जानेवाली सकल राशि तथा अन्य देशों से उसे प्राप्त होनेवाली सकल राशि के अंतर को उस देश का 'भुगतान शेष' कहते हैं।

किसी एक देश को दूसरे देशों से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार तथा अवसर तब आता है जब वह देश उन देशों को माल निर्यात करे, अथवा अपने जहाजों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों तथा कुशल विशेषज्ञों द्वारा अपनी सेवाएँ प्रदान करे अथवा उन देशों के उद्योग व्यापार में अपनी पूँजी लगाकर लाभांश तथा ब्याज प्राप्त करें। ऐसा भी हो सकता है कि उस देश के द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋणों की मूलराशि का उसे भुगतान प्राप्त होता हो या अन्य देशों से ही उसे ऋण स्वरूप राशि मिलती हो। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि अन्य देशों के देशाटक पर्यटक उस देश में आकर माल खरीदें या सेवाओं का उपभोग करें। इन सभी परिस्थितियों में उस देश को अन्य देशों से भुगतान प्राप्त करने का अवसर होगा। इसके विपरीत, संभव है, इन्हीं मदों पर उस देश को अन्य देशों का कुछ भुगतान चुकाना भी हो। इस प्रकार किसी एक तिथि को इन सभी मदों पर एक देश की सफल लेनदारी का अंतर निकालने से उस देश का भुगतान शेष ज्ञात हो जायगा।

वैसे तो देश के बीच इस प्रकार का लेन देन किसी न किसी मद पर निरंतर चलता रहता है, पर यदि किसी निश्चित तिथि को एक देश का विभिन्न मदों पर लेन देन का अंतर निकाला जाए तो अवश्य निम्न परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति सामने आती है:

- (१) यदि किसी देश को अन्य देशों से प्राप्त होने वाली राशि उस देश द्वारा अन्य सभी देशों को चुकाई जाने वाली राशि से अधिक हो तो भुगतान शेष उस देश के 'अनुकूल' अथवा 'पक्ष में' कहा जायगा।
- (२) यदि किसी देश की अन्य देशों से लेनदारी से कम हो तो भुगतान शेष उस देश के 'प्रतिकूल' अथवा 'विपक्ष में' कहा जायगा।
- (३) यदि किसी देश की अन्य देशों के साथ सकल लेनदारी और देनदारी दोनों बराबर हो तो भुगतान शेष 'संतुलित' अथवा 'बराबर' कहा जायगा।

इस प्रकार भुगतान शेष 'अनुकूल', 'प्रतिकूल' व 'संतुलित' या 'पक्ष' में, 'विपक्ष' में और 'बराबर' कहा जाता है। पर इसका संबंध किसी देश विशेष के साथ सापेक्ष अर्थ में व्यक्त करना चाहिए। यह कहना सार्थक नहीं कि भुगतान शेष अनुकूल, प्रतिकूल व संतुलित है; वरन् यह कहना होगा कि अमुक तिथि को या अमुक अवधि में अमुक देश का भुगतान शेष उसके अनुकूल है, प्रतिकूल है अथवा संतुलित है।

भुगतान शेष निकालने में न केवल माल के आयात निर्यात का आधिक्य जिसे 'व्यापार शेष' कहते हैं, ज्ञात किया जाता है वरन् उक्त वर्णित सभी मदों से सकल लेनदारी और सकल देनदारी का अंतर भी ज्ञात किया जाता है। लेन देन के निरंतर क्रम में भुगतान शेष अनिवार्यतः संतुलित हो जाता है पर किसी तिथिविशेष को किसी देश का भुगतान शेष उसके अनुकूल या प्रतिकूल ही पाया जाता है।

किसी देश का अनुकूल तथा प्रतिकूल भुगतान शेष उस देश की आंतरिक आर्थिक स्थिति का परिचायक माना जाता है। यदि भुगतान शेष अनुकूल रहा तो इसका अर्थ होगा उस देश द्वारा निर्यात का बाहुल्य, उत्पादन की प्रचुरता, उद्योग व्यापार की सबलता, विदेशी मुद्रा की कमाई और राष्ट्र के स्वर्णकोश में वृद्धि। इसके विपरीत प्रतिकूल भुगतान शेष का अर्थ होगा आयात का बाहुल्य, व्यापार उद्योग की शिथिलता, उत्पादन में गिरावट, विनियोग का अभाव, विदेशी मुद्रा और राष्ट्र के स्वर्णकोश में कमी। आयोजन व विकास के वर्तमान युग में विकसित देशों से पूँजीगत माल एवं कुशल विशेषज्ञों की आवश्यक मात्रा आयात करने के हेतु यह अनिवार्य हो गया है कि भुगतान शेष देश के पक्ष में अर्थात् अनुकूल बना रहे। आज प्रत्येक देश इसी उद्देश्य के लिये सतत प्रयत्नशील है।[18]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. अरुण, टीजी; निक्सन, एफआई (2010)। "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश: भारतीय अनुभव"। ऑक्सफोर्ड विकास अध्ययन । 28 (1): 19-32. डीओआई : 10.1080/713688302 । आईएसएसएन 1360-0818 . एस2सीआईडी 153421938 ।
2. ^ बुरांगे, जी.; यामिनी, श्रुति (मई 2011)। "भारत की औद्योगिक नीति और प्रदर्शन की समीक्षा" । 7 मई 2020 को लिया गया .
3. ^ घोष और देवैया 2009 , पृ. 226.



4. ^ "मोदी सरकार को वाजपेयी से सीखना चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से धन कैसे पैदा किया जाए" । 29 नवंबर 2019 । 10 मई 2020 को लिया गया .
5. ^ ऊपर जायें: एबी "जनादेश | निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग | वित्त मंत्रालय | भारत सरकार"। 10 मई 2020 को लिया गया.
6. ^ "दीपम | विनिवेश नीति" । digam.gov.in । 23 जनवरी 2022 को लिया गया ।
7. ^ "1991 की नई औद्योगिक नीति की विशेषताएं क्या हैं?" . 4 अक्टूबर 2016 । 7 मई 2020 को लिया गया .
8. ^ ऊपर जायें: एबी "घोष और देवैया 2009, पृ. 225।
9. ^ धमेजा, नंद (2016)। "भारत में पीएसयू विनिवेश: प्रक्रिया और नीति-परिवर्तनशील परिदृश्य"। विजन: द जर्नल ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव । 10 (1): 3-6. डीओआई : 10.1177/097226290601000101 । आईएसएसएन 0972-2629 . एस2सीआईडी 153389192 ।
10. ^ ऊपर जायें: एबी "विनिवेश नीति को आगे बढ़ाने में एनडीए बेहतर है" - द संडे गार्जियन लाइव" । 30 नवंबर 2019। 11 मई 2020 को लिया गया ।
11. ^ "सारांश | निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग | वित्त मंत्रालय | भारत सरकार" । 11 मई 2020 को लिया गया .
12. ^ कक्कड़, भावना (2017)। "भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश का एक अध्ययन (1991-2016)"। एसएसआरएन वर्किंग पेपर श्रृंखला : 5-6। डीओआई : 10.2139/एसएसआरएन.3093570 । आईएसएसएन 1556-5068 . एस2सीआईडी 219382478 ।
13. ^ घोष और देवैया 2009 , पृ. 223.
14. ^ वाधवा, चरण (2005)। "समीक्षा: भारत में विनिवेश: नीतियां, प्रक्रियाएं, प्रथाएं, सुधीर नायब द्वारा"। प्रशांत मामले . 78 (2): 319. जेएसटीओआर 40023945 ।
15. ^ हरजीत सिंह (दिसंबर 2007)। विनिवेश के माध्यम से कॉर्पोरेट पुनर्गठन (एक भारतीय परिप्रेक्ष्य) । न्यू एज इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड। पी। 104. आईएसबीएन 978-81-224-2162-0.
16. ^ गुप्ता, नंदिनी (2010)। "किराने की दुकान का बिल चुकाने के लिए परिवार की चांदी बेच रहे हैं? भारत में निजीकरण का मामला" । किराने का बिल चुकाने के लिए परिवार की चाँदी बेच रहे हैं? भारत में निजीकरण का मामला . 2010 (2): 2. doi : 10.7916/D8XP7CW5 ।
17. ^ जैन, रितिका; सरकार, शुभ्रो (2018)। "भारत में विनिवेश नीति का अनुभवजन्य विश्लेषण: क्या विचारधारा मायने रखती है?" आर्थिक नीति सुधार जर्नल । 22 (4): 2. डीओआई : 10.1080/17487870.2018.1457961 । आईएसएसएन 1748-7870 । एस2सीआईडी 54515568 ।
18. ^ अशरफ, फहमीदा (2007)। "भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार: सीपीआई-एम का समर्थन और चुनौतियाँ"। सामरिक अध्ययन . 27 (4): 68. जेएसटीओआर 45242419 ।



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarase@gmail.com |

www.ijarase.com